

पत्रांक- वित्त(SFC)-12/24(15):...24.9/वि0आ0  
झारखण्ड सरकार  
राज्य वित्त आयोग

राँची, दिनांक...16-12-24

प्रेषक,

अध्यक्ष  
राज्य वित्त आयोग,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

विषय- पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा मांगी गयी सूचनाओं के प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग-- आयोग के पत्रांक-26/वि0आ0, दिनांक-10.04.2024, पत्रांक-112/वि0आ0, दिनांक-03.07.2024, पत्रांक-122/वि0आ0, दिनांक-23.07.2024, पत्रांक-159/वि0आ0, दिनांक-12.09.2024,

महाशय,

उक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा अप्रैल 2024 में प्रथम पत्राचार द्वारा विभागीय Memorandum की मांग की गई थी। साथ ही विभिन्न सूचनाओं की भी मांग प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से की गई थी। कतिपय बैठक आयोजित कर आपका ध्यान भी आकृष्ट किया गया था। लेकिन **अद्यतन विभागीय Memorandum अप्राप्त है।** आप अवगत है कि बिना विभागीय Memorandum के आयोग को कार्रवाई करना संभव नहीं होगा। आप अवगत है कि 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग के द्वारा राज्य वित्त आयोग के लिए प्रतिवेदन प्रेषण एक मानक प्रारूप में समर्पित करने का निर्देश था। यह प्रतिवेदन एक निर्धारित प्रक्रिया एवं सूचनाओं के संकलन के आधार पर तैयार करना है। इसकी पुष्टि 15वें वित्त आयोग ने करने की कृपा की थी। इस क्रम में विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए अप्रैल 2024 के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा सूचना की मांग की गई थी। संबंधित सूचना पूर्व के पत्रों के अतिरिक्त जिन बिन्दुओं को समाहित करना है उसकी प्रति **अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।** अतः याचित सूचनाएं यथाशीघ्र प्रेषित किया जाय। यह संभव है कि अनुलग्नक तथा पूर्व याचित सूचना में Overlapping हो।

AP

2. उक्त के साथ-साथ यथाशीघ्र निम्न सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

- (i) नामित नोडल पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाईल नम्बर/ई-मेल आई डी0 सहित।
- (ii) 74वें संविधान संशोधन के क्रम में शिड्यूल -12 में अंकित 18 विषयों के डेलिगेशन ऑफ पावर की स्थिति तथा उसके Implementation की स्थिति स्पष्ट की जाय।
- (iii) संबंधित डेलिगेशन of power की मोनिटरिंग के लिए विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

3. Property Tax के मामले में राज्य सरकार ने एक Unique नियमावली अधिसूचित की गई है इसके Implementation की स्थिति क्या है ? क्या यह नियमावली Best Practice के रूप में किसी संस्था द्वारा Recognize की गई है ?

4. (i) विभिन्न ULB में कितना प्रतिशत (%) स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति OSR से हो रही है?
- (ii) ऐसे ULBs जो OSR से स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं करते हैं, उसके लिए नगर विकास विभाग की क्या नीति है?
- (iii) क्या नये ULBs तथा Old ULBs तथा MCs and smaller ULBs (नव गठित) को एक ही तरह से Treat किया जा रहा है ? ऐसा treatemnt क्या भविष्य में कतिपय नवअधिसूचित ULB के क्रियाकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा ?
- (iv) कई ULBs में स्थाई कर्मी नहीं है तथा कई में काफी संख्या में है। ULB पेंशन मद में क्या व्यय होता है ?
- (v) क्या ULB कर्मी को पेंशन देने का निर्णय ULB का है या राज्य सरकार का ?
- (vi) वर्तमान में काफी कर्मी नियुक्त किए गए हैं जो ULB में कार्यरत हैं लेकिन उनके Emoluments /वेतन का भुगतान अलग-अलग स्तर से होता है, उसका कारण क्या है?
- (vii) विभिन्न Cadre के पदाधिकारी/कर्मी के Cadre Controlling/ appointing authority कौन है ?

5. (i) ऐसे नगर निगम जिनका गठन वर्तमान कुछ वर्षों में हुआ है उनके आवश्यक Infrastructure की स्थिति यथा कार्यालय भवन एवं अन्य सुविधा की अद्यतन स्थिति क्या है ?
- (ii) ऐसे निकायों को सुदृढ़ करने के लिए क्या व्यवस्था है ? इन निकायों को आत्मनिर्भर (Self reliant) बनाने में क्या योजनाएं चल रही है।
6. (i) निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्था क्या है ? क्या विभाग के पास पर्याप्त प्रशिक्षण संस्थान है?
- (ii) ULBs का कार्य काफी Technical है, ULBs के कर्मियों के Regular Training/Skill Up gradation की क्या व्यवस्था है ?
- (iii) क्या विभाग ने किसी राज्य का Model Study किया है? कोलकाता नगर निगम का Model भी इस बिन्दु के क्रम में देखा जा सकता है।
7. Six Waste Rule Implementation की क्या स्थिति है। ?
8. Carbon Neutral ULB हेतु कोई कार्ययोजना विभाग द्वारा तैयार किया गया है, अगर हाँ तो इससे संबंधित क्या संकल्प /परिपत्र है? Global Warming, Lack of Carbon Neutral Resource, Reduction in green Cover, Ground Water depletion, AQI Level इत्यादि के Restoration के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है?
9. (i) Property tax के मामले में राज्य सरकार के कार्यालय, राज्य सरकार के PSUs तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों तथा केन्द्र सरकार के PSEs से Property Tax संग्रह की क्या व्यवस्था है ? अद्यतन कितना बकाया है ? वर्षवार ब्योरा दें। इस दिशा में क्या प्रयास किया जा रहा है ? क्या 100% Properties ULBs के Database का हिस्सा है, अगर नहीं तो क्या प्रयास किया जा रहा है जिससे यह 100% Coverage हो ?
- (ii) Trade Registration का कार्य ULBs में किया जाता है। क्या यह Professional Tax का अंग है अथवा यह एक Professional Tax से अतिरिक्त activities है? इसकी

Digital Monitoring की क्या व्यवस्था है ? क्या यह Property Tax जैसा गंभीरता से वसूल किया जाता है ?

(iii) विभिन्न OSR की क्या Unified Policy State Government से Notified है ?

10. (i) Water Connection Vrs Property Tax Payee में काफी बड़ा अंतर कई ULB में प्रतिवेदित है। इसको Reconcile करने की क्या व्यवस्था है?

(ii) ULBs पूर्णतः स्वतंत्र होकर Water Supply नहीं कर रही है। अभी भी DWSD द्वारा कई शहरो में Water Supply का निर्माण, रख रखाव एवं संचालन किया जाता है। O&M की Cost भी DWSD द्वारा व्यय किया जाता है। UD&HD or ULBs को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने की क्या योजना है? क्या Water Charges are adequate to meet O&M Cost ? अगर नहीं तो deficit क्या है? Per Householder या प्रत्येक MLD क्या deficit है? इसकी प्रतिपूर्ति कैसे करने की योजना है ?

(iii) वर्तमान में सभी Water Supply का निर्माण, UD&HD की PSE Or ULBs हीं कर रही है। ऐसे में O&M का दायित्व ULB के पास ही होना चाहिए। जल बोर्ड नामक संस्था राज्य स्तर पर गठित हो जैसा अन्य राज्यों में है। इसका अध्ययन करना उपयोगी होगा। क्या विभाग ऐसे Model पर विचार कर रहा है ?

11. (i) ओडिसा, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश में MC Surplus Generate कर रहे है। क्या उसका अध्ययन करना उचित होगा? झारखण्ड में यह काफी ऋणात्मक स्थिति में है।

(ii) झारखण्ड उन 20 राज्यों में है जो Property tax से OSR ज्यादा इकट्ठा करता है। User Charges उसकी तुलना में कम है।

(iii) क्या Stamp duty surcharge ULB/PRI को उपलब्ध होता है ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ? क्या राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के साथ कोई समन्वय किया जा रहा है ?

12. (i) विभाग द्वारा MOHSUA –GOI की Portal- City Finances पर वित्तीय वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 तक का Data Update करने में क्या दिक्कत है ?

(ii) उपलब्ध Data की सत्यता भी विभाग सत्यापित होने की सूचना दें।

(iii) क्या विभाग इस Data का इस्तेमाल नीति निर्माण में कर रहा है ?

13. शहरी क्षेत्रों में Housing Shortage की क्या स्थिति है ?

(i) विभिन्न ULBs वार स्थिति स्पष्ट की जाय ?

(ii) उक्त कमी को दूर करने की सरकार की नीति क्या है ?

(iii) ULB के अतिरिक्त Urban-Rural क्षेत्र के बीच में Development Authorities कार्यरत है, उनकी संख्या/नाम तथा कार्य क्या है ?

विश्वासभाजन,

4/13/24  
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

अध्यक्ष

राज्य वित्त आयोग।

ज्ञापांक:- वित्त(SFC)-12/24(15)-249/वि0आ0

राँची, दिनांक:-16-12-24

प्रतिलिपि :- सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/13/24  
अध्यक्ष

राज्य वित्त आयोग।

ज्ञापांक:- वित्त(SFC)-12/24(15)-249/वि0आ0

राँची, दिनांक:-16-12-24

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची /सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/13/24  
अध्यक्ष

राज्य वित्त आयोग।

## अनुलग्नक-1

### **Data/ Information Required for The Report of the 5<sup>th</sup> State Finance Commission, Jharkhand**

#### **Department of Urban Development and Housing**

- 1) Functional Devolution and Activity Mapping (*Progress towards the delegation envisaged in Articles 243 G and 243 W : this may be assessed (a) in terms of formal notifications issued (b) linked to financial transfers as outlined in Section C of Chapter IV*)
- 2) Status of Implementation of Previous State Finance Commission Recommendations
- 3) Action Taken on Recommendations Relating to Devolution of Finances
- 4) Action Taken on Other Recommendations
- 5) Impact of Implementation of Recommendations of Previous State Finance Commission on State and Local Finances
- 6) Financial Accountability (*Quality of accounts maintained, whether technical guidance and supervision of C&AG has been availed, audit arrangements in place, status of audit of accounts and disposal of audit objections*)
- 7) Administrative Issues in functioning of ULBs
- 8) Role of Parastatals in Managing Functions Listed in XIth and XIIth Schedules and Linkages Between them and the Respective Local Bodies
- 9) Assessment of the Physical Services Provided by the Local Bodies – Level of Services – Availability, Access, Coverage and Quality
  - i. A Quantitative Estimate of Service Deficits with a Brief Account of the Reasons for the Deficit
  - ii. An Inventory of Assets; Current Use and Valuation
  - iii. Basic Services to Slum Settlements; Availability, Coverage, Access, Quality
- 10) *Assessment of Finances of Urban Local Bodies (To be done for Nagar Panchayats, Municipal Council, and Municipal Corporation separately) Analysis of all revenue sources in terms of trends, performance and efficiency as well as estimates of untapped tax potential to be provided*
  - i. Tax Revenue (*Receipts from all sources to be analysed with respect to trend, performance and efficiency. Estimates of untapped potential to be provided*): Taxes on Buildings and Land, Taxes on Non-motorized Vehicles, Taxes on Advertisements and Hoardings, Pilgrim Tax, Any Other Tax, **Unrealised Revenue (Accrual Basis)**
  - ii. Non-Tax Revenue (*Receipts from all sources to be analyzed with respect to trend, performance and efficiency. Estimates of untapped potential to be provided*): User Charges, Fees, Royalty on Minor Minerals, Dividend, Interest, Other
  - iii. Transfers from State Government (*Trend analysis as well as a description of the nature of the transfers to be provided. Also criteria for estimating transfers including grants*)
    - i) Assigned Taxes
    - ii) Share in State Taxes
    - iii) General Purpose Grants
    - iv) Special Purpose Grants
    - v) Transfers for Agency Functions.
  - iv. Transfers from the Central Government
    - i) Finance Commission Grants and Impact - whether such flows were an additionality to State Government flows

- ii) Agency Functions
- v. Capital Account Receipts & Debt Status
  - i) Sources of Receipts eg Loans from State Government, Development Institutions, Market Borrowings, Schematic Transfers, JNNURM, Other ACA etc
  - ii) Trend of Such Receipts
  - iii) Purpose of Such Receipts
- vi. Expenditure on Revenue Account (*Expenditure analysis; component of regulatory and enforcement expenditures, operations and maintenance costs, interest payments and expenditure on services in weaker section areas/slum settlements including area improvement/slum improvement and upgrading and adequacy of such expenditures*)
  - i) Administration
  - ii) Civic Functions: Water Supply, Street Lighting, Sanitation, Solid Waste Disposal
- vii. Expenditure on Maintenance of Community Assets
- viii. Expenditure on Schemes Assigned by the State Government
- ix. Expenditure on Schemes Assigned by the Central Government
- x. Expenditure of Interest
- xi. Expenditure incurred directly by State Government on behalf of Local Bodies (Salaries, Pensions and other liabilities wherever applicable)
- xii. Deferred Expenditure - including unpaid bills, Annuity payments
- xiii. Capital Expenditure
- xiv. Net Budgetary Position
- xv. Review of Fiscal and Financial Management

11) Recording of best practices:

- i) Municipal Corporations
- ii) Municipal Councils
- iii) Nagar Panchayats

12) Assessment of the Gap in Financial Resources and Scheme of Devolution

(B) *Assessment of the Gap (Normative adjustments made as well as assumptions for the same, population projections for the reference period, functional domain and norms for services, financial norms for services, volume of financial requirements for five years)*

*Urban Local Bodies: Nagar Panchayats, Municipal Councils, Municipal Corporations*

(C) *Strategy for Bridging Normative Vertical Gap*

- (j) *Approach to tax and non-tax domain – how can tax and non-tax revenue collection efficiency be improved? What incentives should be put in place? How much more can be mobilised by better application of the existing tax domain?*

- (ii) *Other Approaches – Market; PPP etc*

(D) *Scheme of Devolution*

- a. *Assigned Taxes*
- b. *Share in State Taxes*
- c. *Share of the ULBs and Inter se Distribution*
- d. *Grants-in-aid : Specific Purpose or General Purpose; Timing; Conditionality*

- (13) *Monitoring & Evaluation System (Whether local bodies have in place a framework to monitor the levels of service provided by them in their jurisdiction in comparison to the minimum standards notified)*